



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2012/वैशाख 31, 1934

No. 226]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2012/VAISAKHA 31, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2012

सं. 28/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 377(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, यूएई और ईरान में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यातित सफेद सीमेंट के आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/13/2011-डीजीएडी, तारीख 9 अप्रैल, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 9 अप्रैल, 2012, के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 56/2007-सीमा-शुल्क, तारीख 12 अप्रैल, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 288(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2007 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबद्ध में, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाइट वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसमें इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाइट वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसमें इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 56/2007-सीमा-शुल्क, तारीख 12 अप्रैल, 2007 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 288(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2007 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3. पैरा 2 में किसी बात के होते हुए भी यह अधिसूचना, जब तक कि पहले विखंडित न किया जाए, 11 अप्रैल, 2013 जिसमें यह तारीख भी सम्प्लित है, तक प्रभावी रहेगी”।

[फा. सं. 354/27/2001-टीआरयू (पार्ट-II)]

राजकुमार दिविजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2012

No. 28/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 377(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/13/2011-DGAD, dated the 9th April, 2012, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th April, 2012, had initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'White Cement', originating in, or exported from, UAE and Iran imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), 56/2007-Customs, dated the 12th April, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 288(E), dated the 12th April, 2007, and had requested for extension of anti-dumping duty upto one more year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), 56/2007-Customs, dated the 12th April, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 288(E), dated the 12th April, 2007, namely :—

In the said notification, after para 2, the following shall be added, namely :—

"3. Notwithstanding anything contained in para 2 this notification shall remain in force up to and inclusive of the 11th day of April, 2013, unless revoked earlier".

[F.No. 354/27/2001-TRU (Pt.-II)]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.